किसानों के लिए दुकानों का आवंटन

1371. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उन किसानों के लिए दुकानों का आवंटन करता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ताकि वे अपनी जीविका कमा सके ;

(ख) उनकी आर्थिक और उनको दिए गए मुआवजे की रकम को ध्यान में रख कर उनको छोटी दुकानों का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि किसानों को दिए गए मुआवजे की रकम से पांच या छह गुनी कीमत को बड़ी दुकानों का आवंटन किए जाने से संबद्ध किसान इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी हां (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह कहना सत्य नहीं है कि जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है उनको छोटी दुकानें आवंटित नहीं की जाती हैं । इन श्रेणियों के व्यक्तियों को साधारणत: 20 वर्ग मीटर आकार तक की दुकानें आवंटित की जाती हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किसानों द्वारा प्राप्त किया गया मुआवजे की राशि तथा दुकानों के आवंटन के प्रीमियम के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए दुकान आवंटन के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी मुआवजा की राशि का पूर्वानुमान करना सम्भव नहीं है । यह आशा की जाती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी सुविधा का लाभ उठाने के लिए दुकानों के आवंटी वित्तीय प्रबन्ध करेंगे ।

Slow process of Developmental activity in N.C.R.

3472. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any new projects have been taken by the Ministry of Urban Development in parts of Uttar Pradesh, included in the NCR in the year 1992-93;

(b) if so, the name of the project and its location;

(c) whether Government have noted the very slow process of developmental activity in the National Capital Region; and

(d) if so, the steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) According to the National Capital Region Planning Board no new project has been taken up during 1992-93 in the Uttar Pradesh sub-region of the National Capital Region with the financial assistance of the Board.

(c) and (d) To accelerate the process of development in identified centres in the National Capital Region, Plan provision for schemes sponsored by the National Capital Region Planning Board has been raised to Rs. 200 crores in the Eighth Five-Year Plan and this will be augmented by institutional finance. The participating States/ Union Territory and other concerned Central Ministries have also been requested to allocate adequate resources to supplement the provision so as to increase the availability of land and infrastructure.